



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022020-215854  
CG-DL-E-01022020-215854

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428]  
No. 428]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2020/माघ 10, 1941  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2020/MAGHA 10, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2020

**का.आ. 462(अ).—** केंद्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों की सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के विभिन्न मदों के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित करती है, अर्थात् :-

- (क) भारत सरकार की टकसालें, कोलकाता, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद (मद सं. 11 के अधीन समावेशित) ;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक (मद सं. 12 के अधीन समावेशित);
- (ग) प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय, हैदराबाद (मद सं. 12 के अधीन समावेशित);
- (घ) सिक्योरिटी पेपर मिल्स, हौशंगाबाद (मद सं. 21 के अधीन समावेशित);
- (ङ) बैंक नोट प्रेस सेवाएं, देवास (मद सं. 22 के अधीन समावेशित);
- (च) करेंसी नोट मुद्रणालय, नासिक रोड (मद सं. 25 के अधीन समावेशित)।

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 967(अ), तारीख 22 फरवरी, 2019 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 22 फरवरी, 2019 से छह मास तक की कालावधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि, उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोकहित में अपेक्षित है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यह घोषणा करती है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवाएं होगी।

[सं. एस. 11017/4/2011-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2020

**S.O. 462(E).**—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the following industrial undertakings under the Ministry of Finance which are covered under different items of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall be declared as public utility services for the purposes of the said Act, namely:-

- (a) India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai and Hyderabad (covered under item No.11);
- (b) India Security Press, Nashik (covered under item No. 12);
- (c) Security Printing Press, Hyderabad (covered under item No. 12);
- (d) Security Paper Mill, Hoshangabad (covered under item No. 21);
- (e) Services in the Bank Note Press, Dewas (covered under item No. 22);
- (f) Currency Note Press, Nashik Road (covered under item No. 25).

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 22<sup>nd</sup> February, 2019, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 967(E), dated 22<sup>nd</sup> February, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares from the date of publication of this notification that the said industrial undertakings to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F.No. S.11017/ 4 /2011- IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.